फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 287 प्रभात जयपुर, गुरूवार 21 मई, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

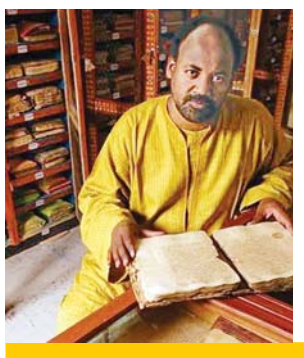

The Librarian Who Risked Life To Save His Books

Hundreds of thousands of ancient manuscripts. One city. One brave librarian who refused to let history burn

Being a grandfather is truly wonderful!

A river that dyes cloth better than any chemical

प्र.मंत्री मोदी ने मंत्रियों से कामकाज पर रिपोर्ट मांगी

प्र.मंत्री ने विदेश यात्रा से लौटते ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मई। पाँच देशों के विदेश दौरे के बाद भारत लौटने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच, मंत्रियों को अपने मंत्रालयों के प्रदर्शन पर प्रस्तुति देने के लिए कहा गया है, साथ ही तत्काल और दीर्घकालिक प्राथमिक कार्यों की सूची भी तैयार करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी केन्द्रीय कैबिनेट के फेरबदल का निर्णय ले सकते हैं।

- मीटिंग में सभी मंत्रियों से उनके मंत्रालय के प्रदर्शन पर प्रैज़ेंटेशन देने को कहा है। समझा जाता है कि इसी के आधार पर वे मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल का निर्णय लेंगे।
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब पर भी चर्चा की जाएगी, जहाँ अगले वर्ष चुनाव होने हैं।
- प्र.मंत्री मोदी मौजूदा ईरान वॉर से उपजे हालात, विशेषकर आर्थिक संकट से निपटने के संबंध में भी मंत्रालयों को निर्देश देंगे।
- सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग के बाद भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरु की जा सकती है और नए पार्टी अध्यक्ष अपनी टीम की घोषणा करेंगे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के परिप्रेक्ष्य में, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री संभवत: मौजूदा पश्चिम एशिया संकट और इसके आर्थिक प्रभाव पर भी चर्चा कर सकते हैं। मंत्रालयों और विभागों को इस स्थिति से निपटने के निर्देश देने की संभावना है। सूत्रों ने कहा, ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर बैठक में विशेष ध्यान दिये जाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रों से सम्बंधित सरकार की नीतिगत सुधारों की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। मोदी ने पहले अगले 10 वर्षों के लिये सुधार प्राथमिकताओं का खाका प्रस्तुत किया था और कहा था कि उनकी सरकार की "सुधार एक्सप्रेस" ने आम नागरिकों के लिए व्यवस्थित एवं महत्वपूर्ण बदलाव सुनिश्चित किए हैं।

कल केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, भाजपा, संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। यह संभवत: नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा अपनी टीम की घोषणा किये जाने के साथ शुरू होगी।

बदलाव के व्यापक होने की संभावना है, जिसमें किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा जैसे अग्रिम संगठन भी शामिल होंगे। केन्द्रीय कैबिनेट का फेरबदल और संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी होने की संभावना है।

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे शी और पुतिन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर, 2026 को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संभवतया नई दिल्ली आ सकते हैं। यह उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन भारत द्वारा ब्लॉक की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

- यह उच्च स्तरीय सम्मेलन 12 और 13 सितम्बर को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है।

चर्चाओं का केन्द्र आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन मजबूती, और वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों के बीच उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रणनीतिक भूमिका पर रहने की उम्मीद है। पुतिन के दौरे की पुष्टि हो चुकी है, जबकि चीनी मीडिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सरकार के पास पिछड़ी जातियों की आबादी का सटीक आंकड़ा होना चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा कि पिछड़ों के कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं बनाने के लिए जातीय जनगणना बेहद जरुरी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मई। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना कराने के महत्व को रेखांकित किया है और कहा है कि सरकार के पास पिछड़ी जातियों के लोगों का सटीक आंकड़ा होना चाहिए।

कोर्ट ने यह बात जाति जनगणना से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कही। न्यायालय का मानना है कि डेटा संग्रह सामाजिक कल्याण नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए बेहद जरूरी है।

अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब विभिन्न समुदायों को दिये जाने वाले लाभ और सामाजिक न्याय से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के सटीक आंकड़े प्राप्त होने पर सरकार संसाधनों का सही आवंटन कर सकती है और कार्यक्रम इस तरह बना सकती है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता बढ़े। वहीं, भरोसेमंद डेटा की कमी हाशिए पर रहे समूहों के उत्थान के प्रयासों में बाधक होती है। विभिन्न राज्यों के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह राय व्यक्त की, इसका अर्थ है कि कोर्ट मानता है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डेटा संग्रह बेहद जरुरी है।
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनज़र सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार देश भर से सटीक आकंड़ें प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयासों पर विचार कर रही है, हालांकि उन्होंने इसकी समय सीमा नहीं बताई, कोर्ट ने बाद की हियरिंग्स में इसके अपडेट देने के निर्देश दिए।

एसओजी ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले को गिरफ्तार किया

आरोपी संदीप सैनी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम में फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति प्राप्त की थी

जयपुर, 20 मई (कासं)। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े और डमी अभ्यर्थियों के जरिए नियुक्ति हासिल करने के मामलों में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने एक और कार्रवाई करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले आरोपी संदीप सैनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले दो महीनों से फरार चल रहा था, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि 6 मार्च 2026 को सवाई मानसिंह अस्पताल के ईएनटी विभागाध्यक्ष एवं नर्सिंग प्रभारी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि जेवीवीएनएल कर्मचारी संदीप सैनी का मेडिकल बोर्ड के समक्ष 'बेरा' एवं 'पीटीए' टेस्ट होना था, लेकिन जांच के दौरान उसके स्थान पर अशोक कुमार जाट नामक युवक अस्पताल पहुंचा था।

- एसएमएस अस्पताल में आरोपी संदीप सैनी की मैडिकल बोर्ड के समक्ष जाँच होनी थी। उसके स्थान पर यह अशोक कुमार जाट का युवक पहुँचा था और पकड़ा गया।

डॉक्टरों ने आधार और जनआधार कार्ड की जांच के दौरान पहचान में गड़बड़ी पकड़ ली, जिसके बाद अशोक कुमार जाट को मौके पर ही पकड लिया गया। मामले में एसओजी थाने में बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच में सामने आया कि आरोपी संदीप सैनी ने पहले बीडीके अस्पताल से 'हेमीपेरेसिस' का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था। बाद में उसने कथित रूप से कूटरचना कर उसकी जगह 'हियरिंग इम्पेयरमेंट' (मूक-बधिर) का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर लिया और दिव्यांग कोटे से जेवीवीएनएल में टेक्निकल हेल्पर-तृतीय के पद पर नियुक्ति हासिल कर ली।

कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार संदीप सैनी का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाना था। रि-मेडिकल में फर्जीवाड़ा उजागर होने के डर से उसने अपने परिचित अशोक कुमार जाट को 10 हजार रुपए देकर अपनी जगह मेडिकल जांच में भेजा था। काम सफल होने पर अधिक रकम देने का भी लालच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमर्यादित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी राष्ट्र से काफी मांगें- भजनलाल

जयपुर, 20 मई । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और अत्यंत निदंनीय है।

- उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रति उपयोग किये शब्द कांग्रेस का पतन दिखाते हैं।

उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति उपयोग किए गए शब्द कांग्रेस की हताशा और पतन को दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानसिक संतुलन खो चुका विपक्ष समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। अमर्यादित शब्दों से देश के सर्वोच्च पदों और देशवासियों की भावनाओं का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को राष्ट्र से सार्वजनिक रुप से माफी मांगनी चाहिए।

विशेष जाँच में 60 पैट्रोल पंप कम पैट्रोल-डीज़ल देते पकड़े गए

उपभोक्ता मामला विभाग ने 20 जिलों के 226 पैट्रोल पंपों का अचानक निरीक्षण किया

जयपुर, 20 मई। आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनज़र सुमित गोदारा, मंत्री उपभोक्ता मामले विभाग, द्वारा राज्यभर में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

5 मई से 18 मई तक विभाग के 23 जांच दलों द्वारा 20 जिलों में कुल 226 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 110 पेट्रोल पंपों के विरुद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 2,21,500 का जुर्माना वसूला गया।

निरीक्षण में 60 पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल एवं डीजल दिए जाने के मामले सामने आए, जिनमें कुल 103 नोजल सीज / बंद किए गए तथा 1,53,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान, कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रति 5 लीटर में 30 मिली से 120 मिली तक कम ईंधन दिया जाना पाया गया।

- विभाग ने अपील की है कि आम नागरिक पैट्रोल व डीज़ल भरवाते समय मात्रा की जाँच अवश्य करें तथा संदेह होने पर 5 लीटर माप से परीक्षण करायें।

विभागीय अनुमान के अनुसार इन अनियमितताओं के कारण उपभोक्ताओं को प्रतिदिन लगभग 211 लीटर पेट्रोल/डीजल कम दिया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21,100 रुपये प्रतिदिन है। यही आंकड़ा मासिक स्तर पर लगभग 6357 लीटर एवं 6,35,700 रुपये तक पहुंचता है।

शॉर्ट डिलीवरी के मामलों में जयपुर में 3 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 12 नोजल; नागौर में 4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 11 नोजल; बाड़मेर में 6 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 10 नोजल; सिरोही में 7 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 9 नोजल; दौसा में 2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 7 नोजल; भरतपुर में 4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 6 नोजल; अलवर में 2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 5 नोजल; जोधपुर एवं पाली में 4-4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 5-5 नोजल सीज किये गये।

सीकर में 1 पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए 4 नोजल; अजमेर एवं भीलवाडा में 3-3 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करते हुए 4-4 नोजल; जैसलमेर में 4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 4 नोजल; बीकानेर में 1 पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए 3 नोजल; कोटा एवं उदयपुर में 2-2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 3-3 नोजल; तथा डूंगरपुर में 3 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 3 नोजल सीज किये गये।

इसी प्रकार झालावाड एवं झुंझुनू में 2-2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 2-2 नोजल एवं सवाई माधोपुर में 1 पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए 1 नोजल सीज किया गया।

इसके अतिरिक्त, 72 पेट्रोल पंपों पर विधिक माप विज्ञान नियमों के उल्लंघन पाए गए, जिनमें 5 लीटर माप सत्यापित नहीं होना तथा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं करना प्रमुख रहा। इन मामलों में कुल 68,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि पेट्रोल एवं डीजल भरवाते समय मात्रा की जांच अवश्य करें तथा संदेह होने पर 5 लीटर माप से परीक्षण करवाएं। किसी भी प्रकार की कम आपूर्ति अथवा अनियमितता की सूचना संबंधित विभागीय कार्यालय को दें।

केरल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

तिरुवनंतपुरम, 20 मई। केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बुधवार को यूडीएफ सरकार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया। उन्होंने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और बंदरगाह जैसे प्रमुख विभाग अपने पास ही रखे हैं। नई कैबिनेट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नितला को गृह और सतर्कता जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ-साथ, तीन अन्य विभाग भी सौंपे गए हैं।

- वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नितला गृह मंत्री बने, मु.मंत्री सतीशन के पास 35 विभाग।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी उद्योग और वाणिज्य सहित, 7 विभाग संभालेंगे।

रेवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के विधायक शिबू बेबी जॉन को वन एवं वन्यजीव संरक्षण और कौशल विकास विभाग सौंपा गया है, जबकि केरल कांग्रेस (जोसेफ) कोटे के मंत्री मोन जोसेफ को सिंचाई, भूजल, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास विभाग दिया गया है।

क्या प.बंगाल फिर से भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा?

प.बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों की उम्मीदें चरम पर पहुँच गई हैं, वे प.बंगाल के सुनहरें अतीत की वापसी की आशा संजो रहे हैं

-अंजन रॉय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मई। अब, जब बंगाल में "डबल इंजन सरकार" सत्ता की ड्राइविंग सीट पर आ गई है, तब राज्य की लंबे समय से ठहरी हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन को लेकर बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई हैं। इसका ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि एक समय बंगाल, देश की अर्थव्यवस्था के अग्रिम मोर्चे पर था। यह बात आज की नई पीढ़ी की याददाश्त से परे है।

यह एक औद्योगिक महाशक्ति हुआ करता था। अधिकांश मैनुफैक्चरिंग उद्योग कलकत्ता और उसके आसपास केन्द्रित थे, क्योंकि यह शहर भारत में विदेशी पूंजी का मुख्यालय था। इसका बंदरगाह देश के निर्यात और आयात दोनों का मुख्य द्वार था, जहां से "भारतीय निर्यात का सुनहरा रेशा," यानी जूट दुनिया भर में जाता था। अधिकांश विदेशी एयरलाइंस कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरती थीं और शनिवार की शाम को विदेश यात्रा पर जाने वाले देश के सबसे महत्वपूर्ण लोग अक्सर यहीं पर एक दूसरे से टकराते नज़र आते थे।

- 35 साल के वामपंथी शासन और उसके बाद तृणमूल के शासनकाल ने प.बंगाल को देश में सबसे गरीब राज्य बना दिया था, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गंभीरता से प्रयास किए जाएं तो हालात बदले जा सकते हैं।
- राज्य के औद्योगिक विकास के लिए लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े पावर प्रोजैक्ट को पुनः शुरु किया जाना जरुरी है।
- मुगलकाल से ही बंगाल खासकर कलकत्ता आर्थिक रूप से समृद्ध था। जगत सेठ जो कभी मुगलों का बैंकर था, उसका मुख्यालय हाउस ऑफ जगत मुर्शिदाबाद में है और कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य को बनाने में हाउस ऑफ जगत सेठ का बड़ा योगदान था, यह बैंकिंग हाउस तब बंद हुआ, जब लॉर्ड क्लाइव ने इससे जो धन उधार लिया था वह नहीं लौटाया।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कलकत्ता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय था। इनमें से दो बैंकों यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया व इलाहाबाद बैंक का ममता बनर्जी के कार्यकाल में विलय कर दिया गया और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के इस फैसले पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की।
- नई सरकार को इन बैंकों के मुख्यालय पुनः कलकत्ता लाना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि राज्य से पलायन कर गए उद्योग वापस लौटने में रूचि दिखाएं।

अब यह सब अतीत की बात हो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर फंसा हुआ है। विदेशी पूंजी ने वाम मोर्चा शासन के पैंतीस वर्षों के शासन के दौरान बंगाल को अलविदा कह दिया था। बंगाल ने अंग्रेजी शब्दकोश को "घेराव" शब्द का तोहफा दिया। वामपंथी नेताओं ने तो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक के उत्तराधिकारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने तक का दुस्साहस किया। शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

बंगाल की बदनामी होने लगी। यह खराब छवि तब और मजबूत हो गई, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टाटा समूह को एक नवनिर्मित फैक्ट्री परिसर से बाहर भगा दिया। स्थिति तब भी नहीं सुधरी, जब उन्होंने ज्योति बसु की पुरानी परिपाटी को दोहराया, जिसके तहत वो हर गर्मियों में ब्रिटेन और यूरोप से विदेशी निवेश आकर्षित करने के दिखावटी मकसद से यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ती थीं।

उस अभियान का सबसे चर्चित दृश्य वो था, जब ममता बनर्जी स्पेन में कहीं अपनी ब्रांडेड "हवाई चप्पल" पहनकर घूमती दिखाई दीं। उसी दौरान उन्होंने एक इस्पात उद्योग परियोजना में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पवार ने मोदी की तारीफ के पुल बांधे

मुंबई, 20 मई। एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मंगलवार शाम मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भी हमेशा देश के भविष्य और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

- शरद पवार ने मुम्बई में एक कार्यक्रम में कहा मोदी विदेशों में भारत का मान बढ़ा रहे हैं।

एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा, राजनीतिक मतभेद भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के आड़े नहीं आने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक सोच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)